

## मोदी सरकार के 18 महीने



# देश की जनता निराश है

गरीबों का पेट भाषणों से नहीं भरा जा सकता. आम जनता की अपेक्षाएं आंकड़ों की बाजीगरी से पूरी नहीं हो सकतीं. हवा-हवाई बातों से युवाओं को रोजगार नहीं मिलता. सिर्फ लोकप्रिय नारे उछालने से सामाजिक बदलाव नहीं आता. जब कल-कारखानों की हालत खराब होने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे, मजदूर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएं, रोजगार मिलना बंद हो जाए और महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि देश में बुरे दिन आने वाले हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 18 महीने यानी डेढ़ साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है. ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नज़र नहीं आता. हर सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन पहले ही साल में सरकार के लक्ष्यों और दिशा का पता चल जाता है. क्या मोदी सरकार मूलभूत परिवर्तन लाने में सफल होगी? क्या वार्दों के मुताबिक विकास संभव है? इस बात को समझने के लिए 18 महीनों के बाद आज मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का आकलन बहुत ज़रूरी है.



मनीष कुमार

**दे** श की जनता ने बड़ी आशा के साथ नरेंद्र मोदी को चुना था. लोगों को लगा था कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से मुक्ति मिलने के बाद राहत मिलेगी.

भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई पर लगाम लगेगी और बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा. नरेंद्र मोदी भी अपने चुनावी भाषण में यह कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन आए क्या? देश के 80 फीसद लोग गरीब है. ज़िंदगी जीने के लिए रोज उन्हे ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है. उनकी तकलीफों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन सरकार से उनकी अपेक्षाएं बहुत कम हैं. इसके ठीक विपरीत देश के 20 फीसद समृद्ध वर्ग की तकलीफें कम हैं, लेकिन उसकी अपेक्षाओं की सूची बहुत लंबी है. हर सरकार को यह तय करना होता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है. दुर्भाग्य से सबसे देश में नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, सबसे जितनी भी सरकारें आईं, उनकी प्राथमिकता में वे 80 फीसद लोग नहीं रहे, जो गरीब हैं. अच्छे दिनों का सही मतलब तो यही था कि मोदी सरकार की प्राथमिकता बदलेगी, लेकिन नई सरकार ने भी वही काम किया, जो 1991 से होता आ रहा है.

समस्या यह है कि गरीब तो परेशान हैं ही,

उद्योगपतियों को भी अब लगने लगा है कि सरकार की दिशा-दशा ठीक नहीं है. मतलब यह कि मोदी सरकार न तो उद्योग जगत को खुश कर पा रही है और न उन 80 फीसद लोगों को राहत दे पा रही है, जिन्हें मदद की वाकई ज़रूरत है. हकीकत यह है कि पिछले 18 महीनों में हर वर्ग निराश हुआ है. किसान परेशान हैं, मजदूर आंदोलित हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई आसमान छू रही है. ऐसे में आर्थिक क्षेत्र में सरकार के सफल होने के सारे संकेत धुंधले होते दिख रहे हैं. लोकसभा चुनाव के पहले भी चौथी दुनिया लगातार यह कहता रहा कि नरेंद्र मोदी नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को ही आगे लेकर जाएंगे. लेकिन, जब उन्होंने अच्छे दिनों का सपना दिखाया, तो देश के बेरोजगार युवाओं और गरीबों के बीच एक आशा जगी. देश के 80 फीसद लोगों के लिए अच्छे दिनों का मतलब सिर्फ इतना है कि महंगाई कम हो और हर युवा को नौकरी मिले. बीते 18 महीनों के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर मोदी सरकार विफल साबित हुई है. वह बाकी सारी बातें कर रही है, लेकिन देश के आम लोगों की असल ज़रूरत पर उसका कोई ध्यान नहीं है.

सरकार बार-बार यह बात जोर-शोर से कह रही है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है और महंगाई कम हो रही है. कहने का मतलब यह कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और लोगों को महंगाई से राहत मिल गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली शायद यह भूल गए कि देश की जनता ने यूपीए सरकार की आंकड़ेबाजी से तंग आकर ही उसे बाहर का

### आंकड़े बोलते हैं

- ➔ वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 फीसद से कम यानी सिर्फ 7.0 फीसद ही रही.
- ➔ अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 5.25 फीसद रही.
- ➔ अक्टूबर 2015 में निर्यात में 17.5 फीसद की गिरावट देखी गई.
- ➔ पिछले साल यानी अक्टूबर 2014 में 25.89 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था.
- ➔ 2015 के अक्टूबर महीने में सिर्फ 21.35 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ.
- ➔ पिछले 14 सालों में करीब 61,000 करोड़पति भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में पलायन कर चुके हैं.
- ➔ मार्च 2015 से अब तक निजी क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश में 30 फीसद की कमी आई है.
- ➔ अप्रैल से सितंबर के बीच औद्योगिक उत्पादन महज 3.94 फीसद की बढ़त दर्ज करा सका.
- ➔ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति भी दयनीय है, वह सिर्फ 2.64 फीसद की दर से बढ़ रहा है.
- ➔ कर्मांडी इंडेक्स प्राइस जुलाई में 3.69 फीसद और अक्टूबर में 5.0 फीसद ही रहा.

रास्ता दिखाया था. वित्त मंत्रालय हो या अन्य दूसरे मंत्रालय, सबने आंकड़ों की बाजीगरी को ही देश चलाना समझ लिया है. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर इस साल आठ फीसद पर पहुंचने वाली है. कुछ महीने पहले देश के विभिन्न अखबारों ने यह खबर दी थी कि भारत की विकास दर चीन से आगे बढ़ जाएगी और वह 7.5 फीसद होने वाली है. अब जबकि नतीजे आने लगे हैं, तो पता चला कि यह महज एक भ्रामक प्रचार था. वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 फीसद से कम यानी सिर्फ 7.0 फीसद हो पाई. अब पता नहीं कि सरकार आंकड़ों का कौन-सा खेल खेलकर वार्षिक विकास दर 7.5 या 8.0 फीसद पर पहुंचाएगी. जबकि विकास के सारे मानक निराशा की ओर इशारा कर रहे हैं.

जुलाई से सितंबर यानी मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लगातार तीसरी बार बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखने को मिली. बिक्री में गिरावट के चलते व्यापार जगत में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका सीधा असर घरेलू निवेश पर पड़ रहा है. ज़्यादा मुनाफे का मतलब ज़्यादा निवेश है. मुनाफे में कमी के चलते घरेलू निवेश कम नहीं लगा रहे हैं. नतीजतन, मार्च 2015 से अब तक निजी क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश में 30 फीसद की कमी आई है. सरकार विदेशी निवेश के बारे में यह तो प्रचारित कर रही है कि उसमें पिछले साल के मुकाबले 37 फीसद

(शेष पृष्ठ 2 पर)





सपा से तालमेल की अटकलें खारिज करने वाली मायावती दूसरी तरफ अकबरुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन से तालमेल को प्राथमिकता दे रही हैं। बसपाई गलियारे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की भुनभुनाहट साफ-साफ सुनी जा सकती है। बसपा में मायावती के अलावा कोई अन्य नेता मुंह नहीं खोलता, लेकिन कुछ नेता गुपचुप तरीके से औवैसी की पार्टी के साथ बसपा के तालमेल को क़रीब-क़रीब तय बताते हैं। यह सब जानते हैं कि मायावती समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुस्लिम वोटों के कारण ही करारा झटका लगा था। इस वजह से बसपा को यह उम्मीद है कि एमआईएम के साथ तालमेल कर उसे मुसलमान मतदाताओं का व्यापक समर्थन हासिल हो सकता है।

## उत्तर प्रदेश : अधर में महागठबंधन

# जब तेवर में हो गरमी, तो रिश्तों में कैसे आए जरमी!



प्रभात रंजन धन

**बि**हार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का प्रयोग दोहराने के दबाव के बीच समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभेद गहराने लगे हैं। तीनों पार्टियां एक-दूसरे पर तलख टिप्पणियां कर रही हैं। इसमें कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कुछ अधिक तलख हैं। बहुजन

समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश महागठबंधन में सपा के साथ शामिल होने की संभावनाओं पर पानी डाल दिया है। मायावती ने ऐसे किसी भी तालमेल में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हो। बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के बसपा या कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना बन सकती है, लेकिन दोनों ही दलों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखने के बयान देने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने तो मुलायम सिंह के जन्मदिवस समारोह पर भी तलख टिप्पणियां कीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने बूते चुनाव लड़ेगी। बसपा ने भी यह कहा कि वह 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसी सभी अटकलबाजियों को खारिज कर दिया।

सपा से तालमेल की अटकलें खारिज करने वाली मायावती दूसरी तरफ अकबरुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन से तालमेल को प्राथमिकता दे रही हैं। बसपाई गलियारे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की भुनभुनाहट साफ-साफ सुनी जा सकती है। बसपा में मायावती के अलावा कोई अन्य नेता मुंह नहीं खोलता, लेकिन कुछ नेता गुपचुप तरीके से औवैसी की पार्टी के साथ बसपा के तालमेल को क़रीब-क़रीब तय बताते हैं। यह सब जानते हैं कि मायावती समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुस्लिम वोटों के कारण ही करारा झटका लगा था। इस वजह से बसपा को यह उम्मीद है कि एमआईएम के साथ तालमेल कर उसे मुसलमान मतदाताओं का व्यापक समर्थन हासिल हो सकता है। अगर उसे 19 प्रतिशत मुसलमानों का समर्थन मिल गया, तो वह 15 प्रतिशत दलित वोटों के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए अकेली मजबूत दावेदार हो जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मायावती को पहले से सवर्णों, खास तौर पर ब्राह्मणों का समर्थन मिलता रहा है।

बहरहाल, कांग्रेस सांसद एवं राहुल के खास पीएल पुनिया का बयान गठबंधन-राजनीति के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। पुनिया कहते हैं कि जनता हर जगह बदलाव चाहती है। उनका इशारा स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ था। महागठबंधन समाजवादी पार्टी के अलग होने को वह भाजपा-सपा के गोपनीय गठबंधन का नतीजा बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस ने फंसला किया है कि उत्तर प्रदेश में वह किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में उसे कांग्रेस सबसे अच्छे विकल्प के रूप में दिख रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री भी इसी अंदाज़ में कहते हैं कि राज्य में सपा और भाजपा दोनों एक साथ हैं। खत्री कहते हैं कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा विरोधी दलों का महागठबंधन फिलहाल शकल में आता नहीं दिख रहा है। खत्री मानते हैं कि सपा और बसपा दोनों ही भाजपा के साथी हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो कांग्रेस कार्यसमिति ही गठबंधन में जाने या न जाने का फैसला लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन वह निजी तौर पर ऐसे किसी भी गठजोड़ में कांग्रेस के शामिल होने के खिलाफ हैं, जिसमें सपा या बसपा हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़े और विधायकों की संख्या 28 से आगे बढ़ाए, इस पर पार्टी में घनघोर मंथन चल रहा है। खत्री ने कहा कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव खुलेआम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और महागठबंधन से अलग होकर उन्होंने भाजपा से अपनी साठगांठ साबित भी कर दी है। बसपा भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। बिहार में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही मुलायम और मायावती ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। सपा के खिलाफ कांग्रेस



## सूबे के लोग गठबंधन-राजनीति के खिलाफ़

**बि**हार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं के आगमन ने आसन्न चुनावों में गठबंधन के प्रयोग की अनिवार्यता महसूस किए जाने का यथार्थ अभिव्यक्त किया। असम में चुनाव है और वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई महागठबंधन की ज़रूरत जता चुके हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल समेत कई राज्यों में चुनाव हैं और दो साल बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार के महागठबंधन की चर्चा ज़रूर है, लेकिन बिहार एवं उत्तर प्रदेश के हालात और राजनीतिक समीकरण अलग-अलग हैं। केन्द्र में भाजपा सत्ता में है और प्रदेश में सपा। दोनों पार्टियों को यह विश्वास नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार बना लेंगी। चूंकि दोनों सत्ता में हैं, लिहाजा दोनों को सत्ता विरोधी मतों का भय सता रहा है। राजनीतिक दलों और नेताओं की राय से अलग राज्य की आम जनता गठबंधन राजनीति के खिलाफ़ है और इसे विकास की राह में बाधक मानती है। बसपा नेता मायावती के इंकार और सपा-बसपा के बीच दुश्मनों जैसे व्यवहार के बावजूद गठबंधन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अतीत में भले ही कई गठबंधन हुए, टूटे और तालमेल के प्रयोग सफल साबित नहीं हुए, लेकिन प्रयोग और दुष्प्रयोग तो जारी हैं। यह भी सत्य है कि बिहार के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों की तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती। बिहार में जनता दल-यू और भाजपा का गठबंधन लंबा चल चुका है। पंजाब में भाजपा और अकाली दल का गठबंधन लंबे अर्से से चल रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे प्रयोगों का आजमाइश-स्थल रहा है, लेकिन यहां गठबंधनों की उम्र अधिक नहीं रही। धुर राजनीतिक विरोधी कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ भी एक सरकार में साथ-साथ रह चुके हैं, लेकिन कोई भी पांच साल तक सरकार नहीं चला सका। उत्तर प्रदेश में गठबंधन राजनीति से सरकार बनाने का प्रयोग पहली बार 1967 में हुआ, जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल (लोकदल) बनाया और सरकार बनाई। उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल हुए, लेकिन वह सरकार एक साल भी नहीं चली। चरण सिंह के बाद 1970 में कांग्रेस से अलग हुए विधायकों ने त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में साझा सरकार बनाने का प्रयोग किया, जिसमें कई अन्य दलों के साथ जनसंघ भी शामिल था, लेकिन सरकार छह महीने नहीं चल सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल से नाराज विभिन्न राजनीतिक दलों ने 1977 में जनता पार्टी के नाम से गठबंधन तैयार किया, इसमें भी जनसंघ शामिल था। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह बहुदलीय सरकार भी कुछ ही दिनों में धराशायी हो गई। 1980 में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में फिर वापस आ गई। 1989 में देश एवं प्रदेश में फिर गठबंधन राजनीति का प्रयोग हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स तोप की खरीद में घोटाटे का आरोप लगाकर उनके मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत कर दी। कांग्रेस विरोधी दलों ने पहले जनमोर्चा और फिर जनता दल के नाम से गठबंधन बनाया। भाजपा भी उन्हें बाहर से समर्थन देने पर राजी हो गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में पांच दिसंबर, 1989 को जनता दल की सरकार बनी, लेकिन यह भी पांच साल नहीं चल सकी। राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। फिर कांग्रेस ने मुलायम को समर्थन दिया, लेकिन वह भी कायम नहीं रहा। इसके बाद हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा सत्ता तक पहुंची, लेकिन अयोध्या में विवादस्पद टांचा ठहरे के कारण कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई। फिर चुनाव हुआ। भाजपा से निपटने के लिए सपा-बसपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन का प्रयोग दोहराया। चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव पांच दिसंबर, 1993 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी तीन जून, 1995 को गेस्ट हाऊस कांड के चलते गिर गई और सपा-बसपा में दुश्मनी भर गई। तब भाजपा और बसपा एक हो गईं। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन यह सरकार भी अधिक समय तक नहीं चल सकी। 1996 में फिर चुनाव हुए, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और बसपा के बीच समझौते के तहत छह-छह महीने के मुख्यमंत्रित्व पर सहमति बनी। मायावती 21 मार्च, 1997 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनीं। सरकार में भाजपा भी शामिल हुई, लेकिन मायावती ने सियासी वेईमानी की मिसाल कायम करते हुए छह महीने बाद कल्याण सिंह को सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया। इस पर भाजपा ने बसपा के विधायकों को तोड़कर कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो 2002 तक चली। 2002 में हुए चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और बसपा ने पुरानी कटुता भुलाकर फिर साझा सरकार बनाने का फैसला किया, लेकिन डेढ़ साल में ही दोनों के बीच राह इतनी बढ़ गई कि 29 अगस्त, 2003 को सरकार जाती रही। फिर मुलायम सिंह ने भाजपा और बसपा के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। 2007 में प्रदेश की जनता ने गठबंधनगामी परिणाम देने से परहेज कर लिया। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनी। 2012 में भी जनता ने यही किया और गठबंधन से परहेज करते हुए समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर उसकी सरकार बनवा दी। कुछ राजनीतिक समीक्षकों को 2017 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से ऐसी ही उम्मीद है। राज्य के आम लोग मानते हैं कि अवसरवादी गठबंधन विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनता है। ■

इतनी तलख हो गई है कि उसने मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश के सैफई में किए गए आयोजन पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मुलायम का जन्मदिवस समारोह दिखावा है और कांग्रेस इस तरह की फिजूलखर्ची की तीव्र भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख के जन्मदिवस पर करोड़ों रुपये खर्च करके भव्य आयोजन किया जाना घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद)

के अध्यक्ष अजित सिंह भी उत्तर प्रदेश में महा-गठबंधन के प्रयोग में रालोद के शामिल होने से इंकार कर चुके हैं। रालोद ने भी कांग्रेसियों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सैफई में करोड़ों रुपये खर्च करके समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह का आलीशान जन्मदिवस समारोह मनाया जाना जनविरोधी कृत्य है। उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। ऐसे में किसानों की तरफ ध्यान देने के बजाय सरकार सैफई में मुलायम सिंह का जन्मदिवस मनाने में लगी रही। यदि समारोह पर खर्च की गई रकम का इस्तेमाल बीज

खरीदने में कर लिया जाता, तो पूरे प्रदेश के किसानों को बीज मुफ्त में मिल जाते। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मसूद अहमद ने कहा कि सिर्फ एआर रहमान की टीम के मुंबई से सैफई आने-जाने का खर्च दो करोड़ रुपये आया। इसके अलावा खाना बनाने वाले गुजरात, बिहार एवं महाराष्ट्र से बुलाए गए थे। इसी से बेहिसाब खर्च का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मसूद ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश को अपनी जागीर समझ लिया है। रालोद महासचिव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि शपथ ग्रहण में पूरे देश के लोग जुटे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश औपचारिकता निभाना भी भूल गए। बिहार जाने के बजाय वह सैफई में संगीतकार एआर रहमान का स्वागत करने चले गए, यह अत्यंत दुःख की बात है।

लब्बोलुबाव यह है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की संभावनाओं के अब तक सोचे गए विभिन्न कोणीय समीकरणों पर फिलहाल विराम लग गया है। अब महागठबंधन के नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाकर इस चर्चा को गर्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के तीखे तेवर देखते हुए सपा प्रमुख मुलायम भी आपा खोने लगे हैं। पिछले दिनों जनेश्वर मिश्र पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज देश को समर्पित करते हुए मुलायम बोले कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करती है। मुलायम ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तिवारी यदि समाजवादी पार्टी में होते, तो समाजवादी नेताओं में उनका नाम अग्रणी होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बने रहने के लिए ऊंची कृपा होनी चाहिए। अगर कृपा नहीं रही, तो आप कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, विडंबना यह है कि जिन्होंने कभी गांव-खेत के दर्शन नहीं किए, वे कांग्रेसी भी अब किसानों का मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं। पगडंडी और मेड़ पर चलने का जिन्हें अभ्यास नहीं, वे किसानों के हितों के संरक्षक बन रहे हैं। दुर्भाग्य से इस देश में ज़्यादातर समय ऐसे ही लोग सत्ता में रहे, जिनका किसानों और खेती से कोई लगाव नहीं रहा। भाजपा और कांग्रेस का कभी खेती, गांव-गरीब से कोई रिश्ता नहीं रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि एक सकारात्मक कृषि नीति के अभाव में किसानों को फसल का लाभप्रद मूल्य तो मिला नहीं, सकल घरेलू उत्पादों में कृषि का हिस्सा भी कम होता गया। चौधरी कहते हैं कि मुलायम सिंह बराबर इस बात पर ज़ोर देते आए हैं कि किसानों की तरक्की के बिना देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए रखा था। प्रदेश में 2012 के चुनाव के बाद बहुमत से बनी समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए रखा और वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष घोषित किया। जब भाजपा नीत केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, तो अखिलेश ने स्मार्ट विलेज की अवधारणा रखी। ■



महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने पांच विधायकों पर एक मंत्री का सूत्र इस्तेमाल किया। यदि इसी सूत्र के आधार पर महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाता, तो चार महिला विधायकों को मंत्री पद मिलना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के सभी पांच चरणों को मिलाकर देखें, तो आप पाएंगे कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी 59.92 फीसद रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी, जिसके चलते मंत्रिमंडल के गठन के समय महिला विधायकों की उपेक्षा कर दी गई।

## सातवां वेतन आयोग आसान नहीं सरकार की राह

आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम तनखाह को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया है। जबकि सचिव स्तर के अधिकारियों की तनखाह को 80 हजार से बढ़ाकर लगभग सवा दो लाख कर दिया गया है। इसके अलावा सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन छोटे कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट में केवल अधिकारियों की तनखाह में बड़ा इजाफा किया गया है जबकि कर्मचारियों की तनखाह में मामूली।

### अरुण तिवारी

**ज**स्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी 900 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंप दी है। सातवें वेतन आयोग का यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठन किया था। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वह निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, इसके बाद उसे चार महीने का समय और दिया गया था। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 प्रतिशत, वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में कुल 63 प्रतिशत, पेंशन में 24 प्रतिशत और औसतन 23.55 प्रतिशत इजाफे की अनुशंसा की है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी। इसका फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को होगा। इन अनुशंसाओं के लागू होने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 1.02 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च में से 74 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 28 हजार करोड़ रुपये रेल बजट से खर्च किए जाएंगे। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.65 प्रतिशत होगी, छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में यह वृद्धि जीडीपी का 0.7 प्रतिशत थी। आयोग ने सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुशंसा की है।

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी, जिससे महंगाई में बढ़ोत्तरी होगी। जिस तरह छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद दोपहिया-चारपहिया वाहनों और कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में इजाफा हुआ था, कुछ वैसा ऐसा ही कुछ सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के बाद होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुपहिया वाहनों की मांग में 2 से तीन प्रतिशत और चारपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सरकार के ऊपर पहले से ही फिस्कल डेफिसिट को कम करने का दबाव है, ऐसे में पहले

सेना में वन रैंक, वन पेंशन को लागू करने के बाद दबाव बढ़ा है। इसके बाद सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से सरकार के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(एफआरबीएम) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाना आसान नहीं होगा, ऐसे ही सरकार ने इस वित्त वर्ष सेवा कर को पहले 12.36 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया, इसके बाद इसमें 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है। जो बात अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कही थी कि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2015-16 में जीडीपी का 3.9 प्रतिशत, 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और 2017-18 में तीन प्रतिशत रहेगा, लेकिन सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद सरकार इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। वर्तमान में राजकोषीय घाटा 4.1 प्रतिशत है। ऐसे में सरकार के पास केवल चार रास्ते हैं। पहला वह कर में वृद्धि करे, दूसरा, अपने खर्च में कटौती करे और तीसरा, कर्ज ले या एफडीआई के लिए रास्ता खोले। एनडीए सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में कई बार यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि हो चुकी है, सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं, ऐसे में रेल बजट पर पड़ने वाला 28 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ की पूर्ति सरकार के लिए कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। किराए और माल भाड़े में वृद्धि करके सरकार यात्रियों के लिए किसी तरह की



सुविधाओं का इजाफा नहीं कर पाएगी। ऐसे में रेलवे में एफडीआई लाना ही उसके पास एकमात्र और अंतिम रास्ता बचता है जिसे वह अपनाएंगे। ऐसे ही अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे में एफडीआई के संकेत दे चुके हैं।

आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम तनखाह को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया है। जबकि सचिव स्तर के अधिकारियों की तनखाह को 80 हजार से बढ़ाकर लगभग सवा दो लाख

कर दिया गया है। इसके अलावा सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन छोटे कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट में केवल अधिकारियों की तनखाह में बड़ा इजाफा किया गया है जबकि कर्मचारियों की तनखाह में मामूली। इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का अनुपात 1:12 हो जाएगा। हालांकि न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी इसे 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहे थे। आयोग ने कर्मचारियों का परफॉर्मस रिलेटेड पे(पीआरपी) लागू करने का प्रस्ताव दिया है। आयोग का मानना है कि सरकार को पीआरपी को एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करना चाहिए। ताकी सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी बेहतरिन परफॉर्मस दें। पर ये भी सिफारिश की है कि 20 साल सही परफॉर्मस नहीं करने वाले का इन्कीमेंट रोक दें। दो वजहें हैं। पहली- जब भी कोई नौकरी जवाइन करता है तो कुछ साल प्रोबेशन पर रहता है। उसी के बाद वास्तविक जिम्मेदारी शुरू होती है। दूसरी- उसे परफॉर्मस दिखाने का पर्याप्त समय मिले, ताकि वह कोई बहाना न बना सके।

केंद्रीय कर्मचारियों की तनखाह के बढ़ने से कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स में 6 से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिसका महंगाई से सीधा वास्ता है।

यदि मांग और आपूर्ति के बीच सही संतुलन नहीं बनाया गया तो महंगाई के रूप में जनता को खामियाजा भुगतान पड़ेगा। हालांकि औद्योगिक विकास दर इससे जरूर बढ़ेगी लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं, उद्योगपतियों को होगा। आयोग ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन देने, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने, वेतन निर्धारण के लिए ग्रेड पे और पे बैंड की व्यवस्था खत्म करने, पैरा मिलेट्री फोर्सेज को भी शहीद का दर्जा देने, सैन्य सेवाओं के कर्मचारियों की तनखाह दोगुनी करने (केवल सेना पर लागू होगा) जैसी अनुशंसा की है। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल अधिकतम 33 साल तय किए जाने की अनुशंसा भी की है। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी। इस तरह की अनुशंसाओं का भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।

हालांकि सरकार आयोग की कितनी अनुशंसाओं को लागू करती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके अलावा सरकार अपने आय और व्यय में किस तरह संतुलन लाएगी यह फरवरी में आने वाले बजट में दिखाई पड़ जाएगा।

feedback@chauthiduniya.com

### महत्वपूर्ण अनुशंसाएं

1. बेसिक सैलरी में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
2. न्यूनतम वेतन 18,000 हजार रुपये हो जाएगा।
3. भत्तों में 63 फीसद की बढ़ोतरी होने के साथ ही पेंशन में 24 फीसद बढ़ोतरी।
4. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार पर एक लाख दो हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
5. सातवें वेतन आयोग के तहत की गई ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी।
6. पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा।
7. सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा।
8. फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को होगा।
9. पे-बैंड और ग्रेड-पे की प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश।
10. सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की सिफारिश।
11. शॉर्ट सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोड़ने की अनुमति होगी।

## बिहार मंत्रिमंडल में महिलाओं को मिले पूरा हक

महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरी 25 महिला उम्मीदवारों में से 23 ने जीत दर्ज की। नोखा की विधायक अनीता देवी राजद कोटे से मंत्री बनाई गई, जबकि जदयू कोटे से चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा मंत्री बनीं। महा-गठबंधन के तीसरे घटक दल कांग्रेस की चार महिला विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनने वाली दोनों महिला विधायकों ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है।

### दिव्या त्रिपाठी

**द**ेश की आधी आबादी ने स्वयं को हर क्षेत्र में साबित किया है। सीमा की सुरक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सभी जगहों पर महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी नजर आती हैं। महिलाएं समाजसेवा में पीछे नहीं हैं, राजनीति में पीछे नहीं हैं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के बावजूद अक्सर उन्हें नेतृत्व की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। बिहार सरकार के गठन में महिला विधायकों की उपेक्षा इस बात का ताजातरीन उदाहरण है। राज्य की आधी आबादी ने मतदान में सबसे ज्यादा भागीदारी की। चुनाव में महिलाओं का समर्थन महागठबंधन को मिला, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं का चेहरा पीछे नजर आ रहा है। महिलाओं की उम्मीदों को ग्रहण तब लगा, जब सरकार गठन के समय सिर्फ दो महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही विभागों का भी बंटवारा



हो चुका है।

महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरी 25 महिला उम्मीदवारों में से 23 ने जीत दर्ज की। नोखा की विधायक अनीता देवी राजद कोटे से मंत्री बनाई गई, जबकि जदयू कोटे से चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा मंत्री बनीं।

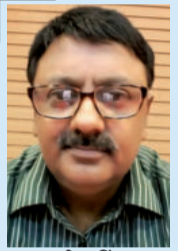
महागठबंधन के तीसरे घटक दल कांग्रेस की चार महिला विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनने वाली दोनों महिला विधायकों ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है। पिछली बार मंत्री रहें लेसी सिंह एवं बीमा भारती को इस बार नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। चुनाव के दौरान राज्य की महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार का जबरदस्त समर्थन किया, क्योंकि वे नीतीश सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं। खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के चलते वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करती रही हैं। राजद के साथ गठबंधन के बावजूद महिलाओं ने नीतीश कुमार पर विश्वास करते हुए महागठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया।

महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने पांच विधायकों पर एक मंत्री का सूत्र इस्तेमाल किया। यदि इसी सूत्र के आधार पर महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाता, तो चार महिला विधायकों को मंत्री पद मिलना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के सभी पांच चरणों को मिलाकर देखें, तो आप पाएंगे कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी 59.92 फीसद रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी, जिसके चलते मंत्रिमंडल के गठन के समय महिला विधायकों की उपेक्षा कर दी गई। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरसंभव प्रयास किए। पंचायती राज्य एक्ट 2006 के तहत महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना। क्या मंत्रिमंडल के गठन में राज्य की महिलाओं की उपेक्षा नहीं की गई? राजनीति में जब-जब महिलाओं को समुचित भागीदारी देने की बात आती है, तो यह सवाल किसी न किसी तरह हाशिये पर डाल दिया जाता है। आखिर आधी आबादी को बराबरी का हक कब मिलेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में पूर्ण शराबबंदी

## नीतीश के साहस को सलाम



सरोज सिंह

पटना में 9 जुलाई, 2015 को आयोजित ग्रामवार्ता कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपने संबोधन के बाद बैठ चुके थे। इसी बीच एक महिला की आवाज गूंजी-मुख्यमंत्री जी, शराब बंद कराइए घर बर्बाद हो रहा है। कई और महिलाएं बोले लगीं। सीएम उठे, माइक पर बोले अगली बार सरकार में आए, तो कर दूंगा। नीतीश कुमार के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीतीश कुमार की इस घोषणा को विपक्षी दलों ने चुनावी घोषणा कह कर बहुत ही हल्के में लिया। चुनाव के समय भी बार-बार विरोधी दलों ने इस बात को लेकर नीतीश कुमार पर ताना जड़ा कि नीतीश केवल वोट लेने के लिए शराबबंदी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस एलान को न केवल अपने सात निश्चय में शामिल किया, बल्कि सरकार बनने के बाद अपने पहले ही सार्वजनिक भाषण में पहली अप्रैल, 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध का एलान कर दिया। मध्य निषेध दिवस पर नीतीश कुमार ने कहा कि शराब से गरीबों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। कुछ समय पहले मैंने श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की मांग पर वादा किया था कि अगली बार आए तो शराब बंदी लागू कर दूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। एक अप्रैल से ऐसी नीति लागू करेंगे कि

सरकार के आला अफसर भी दूसरी जगह जारी शराबबंदी के मॉडल की समीक्षा में जुट गए हैं। नीतीश कुमार इस बात को जान रहे हैं कि अगर वह शराबबंदी लागू करने में सफल रहे तो फिर जिस तरह महादलितों का एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया, ठीक उसी तरह महिलाओं का भी एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी कोशिश है कि शराबबंदी का हाल गुटखा जैसा न हो।

गरीब के जीवन पर शराब के कारण छाने वाला अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयोग होगा कि नशा सेवन के कारण आमदनी का पैसा शिक्षा पर खर्च हो, पोषणयुक्त भोजन पर खर्च हो, न कि नशा सेवन पर। ऐसे परिवार की महिलाओं को शराबबंदी से खुशी मिलेगी और परिवार का विकास तेजी से होगा। मैंने मुख्य सचिव और उत्पाद विभाग को नई नीति बनाने का आदेश दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वाले दो तरह के होते हैं। पहला वे लोग, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वे महंगी शराब पीते हैं। ऐसे लोगों को शराब से होने वाले

नुकसान की जानकारी रहती है, फिर भी वे शराब पीते हैं, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे वे लोग हैं, जो देशी और मसालेदार शराब पीते हैं। कम आमदनी वाले लोग इस तरह की शराब ज्यादा पीते हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी की घोषणा का व्यापक स्वागत हुआ, लेकिन इस फैसले ने कई तरह की आशंकाओं को भी जन्म दिया। गौरतलब है कि 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शराब पर रोक लगायी थी, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। तस्करी तथा कई अन्य व्यवहारिक दिक्कतें सामने आईं। बहुत मायनों में यह राजनीतिक मसला भी बना। अंततः डेढ़ साल बाद नई सरकार ने रोक हटा दी। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रदेश में पान मसाले पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। हां, अंतर यह आया है कि पहले यह दुकानों में खुलेआम बिकता था, पर अब दुकानदार इसे छिपा कर ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। जहां तक छिपा कर बेचने की बात है तो यह केवल पटना में ही है। दूसरे शहरों में यह खुलेआम बेचा जा रहा है। इसी आधार पर आशंकाओं ने जन्म लिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि नीतीश ने अपने अधिकारियों से साफ कर दिया है कि शराबबंदी में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के आला अफसर भी दूसरी जगह जारी शराबबंदी के मॉडल की समीक्षा में जुट गए हैं। नीतीश कुमार इस बात को जान रहे हैं कि अगर वह शराबबंदी लागू करने में सफल रहे तो फिर जिस तरह महादलितों का एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया, ठीक उसी तरह महिलाओं का भी एक

राज्य में शराब की 5967 दुकानें

5967 5446 2471 1434

स्वीकृत दुकानें बन्दोबस्त दुकानें देशी शराब की दुकानें विदेशी शराब की दुकानें

521 दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं हो सकी

10 वर्षों में 1255 प्रतिशत बढ़ा राजस्व

वर्ष	राजस्व राशि करोड़ रु. में
2005-06	295
2009-10	1099
2010-11	1543
2011-12	2045
2012-13	2432
2013-14	3173
2014-15	3220
2015-16	4000 लक्ष्य

अक्टूबर 2015 तक 2240 करोड़ रुपये की वसूली

सालाना 1410 लाख लीटर से अधिक खपत

देशी शराब	विदेशी शराब	बीयर
990.36 लाख लीटर	420 लाख लीटर	512.37 लाख लीटर

इन राज्यों में है रोक

गुजरात, नागालैंड, लक्षदीप तथा मणिपुर के कुछ हिस्सों में, केरल में 30 मई 2014 के बाद से शराब दुकानों को लाइसेंस मिलना बंद हो गया है। ऐसा अगले कुछ वर्षों में पूर्ण पाबंदी के मकसद से हो रहा है।

यहां पहले था प्रतिबंध

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम में शराबबंदी हुई थी, लेकिन कारगर न हो सकी। अब यहां शराब बिकती है।

बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी कोशिश है कि शराबबंदी का हाल गुटखा जैसा न हो। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि पुलिसवाले की मनमानी काफी बढ़ जाएगी और बढ़े हुए दाम पर चोरी-छिपे शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इस आशंका में दम भी है, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि इस तरह की बातें सामने न आए। अन्यथा यह पूरा मिशन ही भटक जाएगा और नीतीश कुमार के इमेज को भी दाग लगेगा। फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि शराबबंदी का एलान कर नीतीश कुमार ने साहस का काम किया है और कोई 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है।

feedback@chauthiduniya.com

अपर्णा के स्टैंड से सकते में सपा

## मुलायम की बहू ने आमिर को धिक्कारा

वैष्णवी वंदना

समाजवादी पार्टी की नीतियां मुलायम परिवार के अंदरूनी विरोधाभास में खंडित और प्रतिखंडित होती रहती हैं और कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी भ्रम की स्थिति बनती रहती है। सपा कार्यकर्ताओं और सामान्य नेताओं को यह समझ में ही नहीं आता कि वे देश-प्रदेश के जरूरी मसलों पर मुलायम परिवार से आने वाले परस्पर विरोधी बयानों में आखिर किस तरफ खड़े हों। सहिष्णुता और असहिष्णुता के ताजातरीन सियासी मसले पर भी ऐसी ही स्थिति बन गई है। मुलायम परिवार का कोई सदस्य असहिष्णुता के आरोपों के पक्ष में खड़ा है तो कोई असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों को धोने में लगा है। समाजवादी पार्टी से गहरे जुड़े महाकवि गोपाल दास नीरज असहिष्णुता के मसले पर पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों को आडम्बरी बता कर अपनी खुली प्रतिक्रिया जता चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसके विपरीत रहा है। नीरज ने कहा था कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार सस्ती राजनीति कर रहे हैं। इन साहित्यकारों को कांग्रेस के राज में पुरस्कार मिला था और अब वही इनसे ये पुरस्कार लौटाने का काम करवा रही है। इससे कांग्रेस की ही बदनामी हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने असहिष्णुता का आरोप लगाने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान को आड़े हाथों लिया है और देश के लोगों द्वारा मिले प्रेम और समर्थन का ऐसा प्रतिकार करने के खिलाफ आमिर की खूब निंदा की है। मुलायम के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव के इस स्टैंड से सपा नेतृत्व सकते में है। समाजवादी पार्टी ने इस मसले में आमिर खान का पक्ष लिया था और पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी आया था। मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने आमिर खान के खिलाफ जो कमेंट लिखे, वह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और उस पर देशभर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। अपर्णा ने अपने फेसबुक-टाइमलाइन पर लिखा, यह सत्यापित हो गया है कि आमिर खान सिर्फ अभिनेता हैं, जो कि रंग दे बसंती और मंगल पांडे जैसे देशभक्तों के किरदार निभाने के बावजूद अपनी पत्नी को देश प्रेम नहीं समझा पाये। हमारी गलती है कि आमिर से इतनी बड़ी अपेक्षा की। जय हिन्द, जय भारत! इससे पहले भी अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ कर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। आमिर पर अपर्णा के कमेंट से यह जाहिर हुआ कि फिल्म अभिनेता आमिर खान को देश में असहनशीलता बढ़ने जैसा महसूस होना और उनकी पत्नी किरण राव द्वारा इस डर से देश छोड़ने की बात करना उन्हें अत्यंत नागवार गुजरा है। उन्हें आमिर



और उनकी बीवी किरण राव की यह बातें बेमानी और फिजूल लगती हैं, लेकिन अपर्णा यादव जो महसूस कर रही हैं, वहीं उनके ससुर मुलायम सिंह यादव ऐसा महसूस नहीं कर रहे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आमिर खान के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि आमिर एक बड़े अभिनेता हैं और केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मुलायम ने कहा था कि आमिर खान को कहीं चोट लगी होगी, किसी बात पर वे आहत हुए होंगे, तभी उन्होंने असहिष्णुता पर इस तरह का बयान दिया है। हर किसी को अपनी-अपनी राय देने का अधिकार है। अपने विचारों को रखने की इस स्वतंत्रता को ही लोकतंत्र कहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी आमिर खान के बयान का समर्थन करते हुए एक हाथ आगे बढ़ कर कहा था कि फिल्म अभिनेता को किसी वजह से देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। वह बड़े आराम से उत्तर प्रदेश में आकर रह सकते हैं। उन्हीं की बहू ने आमिर खान को पूरी तरह गलत करार दिया। सपा नेता आजम खान ने आदतन क्रीज से बाहर निकल कर

खलेते हुए फटाफट आमिर खान के समर्थन में चिट्ठी लिख डाली। अपने अलग विचार और तेवर से मुलायम की बहू पहले भी समाजवादी पार्टी को हतप्रभ करती रही हैं। बीफ वाले मसले पर सपा नेतृत्व के स्टैंड के खिलाफ जाकर उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि गाय का मांस खाना जायज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका यह विचार किसी धर्म विशेष पर कमेंट नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया था कि गाय हमारी मां के समान है और इसका मांस खाना जायज बात नहीं है। गरीबों के बीच गाय काटने पर जो लोग आग भड़काते हैं, वे वे अमीर हैं, जो अपनी थाली में गोमांस परोसे हैं। यदि अमीरों के पैसों से गाय का मांस खया जाएगा तो हिंदुस्तान कल तालिबान कहल-एगा। मेरा ये बयान किसी विशेष धर्म पर टिप्पणी नहीं है। हमें अपनी मां को बचाना ही होगा। इस ट्वीट को अपर्णा ने अपने फेसबुक पेज से भी लिंक किया था, जिसमें हर धर्म से जुड़े लोगों के काफी कमेंट आए। दादरी मसले पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के यूएन जाने की धमकी पर जब सपा नेतृत्व ने आजम के बयान से पल्ला झाड़ लिया और इसे उनका निजी

विचार बताया, तब भी अपर्णा ने विरोधी लाइन लिया और आजम का समर्थन कर डाला। तब अपर्णा ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय फोरम है। ऐसी घटनाएं यूएन में जाएं या नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को लिखे आजम के पत्र से भारत की छवि खराब नहीं होती। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की कुछ ही दिनों पहले गोरखनाथ मंदिर के मुख्य महंत योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात ने भी देश का ध्यान खींचा था। अपर्णा ने गोरखनाथ धाम जाकर योगी से मुलाकात की थी और दिवंगत महंत अवैद्यनाथ के प्रति संवेदना जताई थी। अपर्णा ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए थे और महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफलाइटिस पीड़ितों से मुलाकात कर उन्होंने पीड़ितों के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जा रहे इंतजामों की प्रशंसा की थी। सपा नेताओं को अपर्णा द्वारा योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा अत्यंत नागवार गुजरी थी।

feedback@chauthiduniya.com





भारत में लगभग साढ़े छः करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अगर बात गांवों की की जाये तो गांवों में आज भी पुराने और परम्परागत तरीकों से खाना बनाने का काम प्रतिदिन होता है। गांवों में अभी तक लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं उपलों, कोयलों और केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करती हैं। खाना बनाते वक्त लकड़ी, केरोसिन और कोयले से निकलने वाला धुआं रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए फेफड़ों, आंखों समेत कई जानलेवा बीमारियां लेकर आती है।

# धुएं के ज़हर से बचाता है आधुनिक कोयला

किसानों ने आधुनिक कोयला बनाने के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील से बने कुकिंग स्टोव का भी निर्माण किया है, जिसमें बिना किसी झंझट और धुएं के स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा सकता है।



मानसी बत्रा

feedback@chauthiduniya.com

**म**नुष्य को जीवन देने वाली हवा को आज चारों ओर फैल रहे प्रदूषण ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि सांस लेने के लिए भी वह महफूज नहीं है। बढ़ते हुये कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई गाड़ियों का धुआं, संयंत्रों में बढ़ती कोयले की खपत, ये सभी मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। सफलता और विकास को पाने के लिए आज हम जो दूसरी जरूरी बातें भूल चुके हैं, वह है बेहतर स्वास्थ्य। यह बगैर स्वच्छ पर्यावरण के संभव नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में लगभग 13 शहर भारत के ही हैं। प्रदूषण के कारण कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिये बड़ा खतरा बनती जा रही हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग साढ़े छः करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अगर बात गांवों की की जाये तो गांवों में आज भी पुराने और परम्परागत तरीकों से खाना बनाने का काम प्रतिदिन होता है। गांवों में अभी तक लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं उपलों, कोयलों और केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करती हैं। खाना बनाते वक्त लकड़ी, केरोसिन और कोयले से निकलने वाला धुआं रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए फेफड़ों, आंखों समेत कई जानलेवा बीमारियां लेकर आता है। ग्रामीण महिलाओं को इन बीमारियों से सचेत करने के लिए राजस्थान के मोरारका फाउंडेशन ने आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुवात की है। हर साल लगभग 1.6 मिलियन लोग इसके कारण पैदा होने वाले धुएं



और प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। लगभग 10 लाख बच्चों की हर साल मौत का कारण भी ये धुआं और प्रदूषण ही हैं। मोरारका फाउंडेशन किसानों को रोजगार और बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है और इस बार खेतों के बचे कचरे से कोयला बनाने की तकनीक सीखाकर किसानों को मोरारका फाउंडेशन जागरूक कर रहा है। खेतों के बचे कचरे से आधुनिक कोयला तैयार किया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिये भी फायदेमंद होता है। आधुनिक कोयला बनाने की आधुनिक तकनीक और नवलगढ़ के किसान बचे हुए कचरे से आधुनिक कोयला बना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों ने

## कोयला बनाने की तकनीक

1. किसी भी प्रकार की सूखी पत्तियां, लकड़ी, सूखी घास व खेत का कचरा काम में लिया जा सकता है।
2. फसल काटने के बाद खेत में छोड़े हुए कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाता है और उसे चिमनी से ढक दिया जाता है।
3. चारकोल का भूरा और आटे के बाइंडर (गिला आटे) को मिवस कर दिया जाता है।
4. मिवसचर को मशीन में डालकर छोटे-छोटे कोयले के टुकड़े तैयार किए जाते हैं।

आधुनिक कोयला बनाने के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील से बने कुकिंग स्टोव का भी निर्माण किया है, जिसमें बिना किसी झंझट और धुएं के स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा सकता है। खाना पकने तक महिलाएं अपने अन्य काम निपटा सकती हैं। कुकिंग स्टोव में खाना मात्र 45 मिनट में तैयार हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण के चारे में अगर लोगों को जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। जागरूकता के अभाव में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिसे हम जान नहीं पाते। थोड़ा बहुत बदलाव करके ग्रामीण लोगों के खाना बनाने के कार्य को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की यह कोशिश अच्छा कदम है। ■

# तस्वीरों में यह सप्ताह

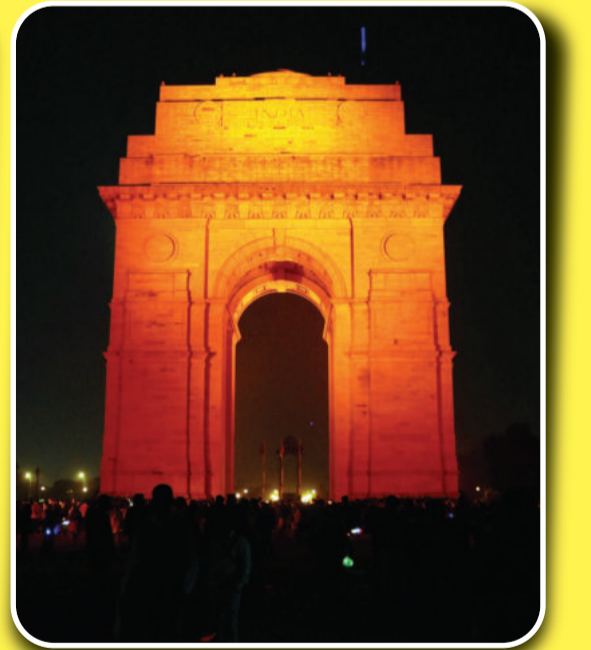
सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा



● नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उमड़े लोग।



● सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित क्वीन इंडिया मूवमेंट में बच्चों के साथ भाजपा सांसद हेमा मालिनी।



● महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नारंगी रंग में रंगा इंडिया गेट।



● द्वारका (नई दिल्ली) में कार फ्री डे के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।



● इंदिरा गांधी के 98वें जन्मदिवस के मौके पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।



● जंतर-मंतर पर आईएसआईएस के मुखिया बगदादी और सपा नेता आजम खान का पुतला फूंकते हुए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता।









आसियान सम्मेलन के दौरान एक बेहतरीन पहल आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के रूप में सामने आई. मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रज़ाक ने आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के गठन की औपचारिक घोषणा की. कुआलालंपुर में आयोजित दसवें आसियान सम्मेलन में यह घोषणा की गई. ईसी अगले वर्ष प्रभाव में आएगा और इसका मकसद आसियान के दस सदस्य देशों के बीच सहयोग को अगले दौर में ले जाना है. इसके तहत आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे आगे चलकर श्रमिकों के बेरोकटोक एक-दूसरे देश में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.

# आसियान से उठी आतंकवाद के खिलाफ आवाज़



चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद अब किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है. उन्होंने कहा कि अक्सर इस मंच पर हम सोचते हैं कि आतंकवाद हमारे आसपास की समस्या है, लेकिन पेरिस, अंकारा, बेरूत, माली और रूसी विमान पर हुए हमलों से स्पष्ट है कि आतंकवाद की परछाई ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें नए संकल्प और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा. किसी भी देश को आतंकवाद का इस्तेमाल या समर्थन नहीं करना चाहिए. आतंकी गुटों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए. उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं होनी चाहिए. उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलनी चाहिए. उनकी पहुंच हथियारों तक नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा, आसियान सम्मेलन के दौरान एक बेहतरीन पहल आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के रूप में सामने आई. मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रज़ाक ने ईसी के गठन की औपचारिक घोषणा की. कुआलालंपुर में आयोजित दसवें आसियान सम्मेलन में यह घोषणा की गई. ईसी अगले वर्ष प्रभाव में आएगा और इसका मकसद आसियान के दस सदस्य देशों के बीच सहयोग को अगले दौर में ले जाना है. इसके तहत आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे आगे चलकर श्रमिकों के बेरोकटोक एक-दूसरे देश में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे से भी अलग से मुलाकात की और जापान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. अबे ने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान संबंधों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत-जापान के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का विस्तार हो.



इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे से भी अलग से मुलाकात की और जापान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. अबे ने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान संबंधों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत-जापान के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का विस्तार हो.

आसियान सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे. उन्होंने सिंगापुर में भारतीय लोगों के बीच भाषण भी दिया. उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ एक विश्वास से देख रहा है. इस भाषण की खास बातें ये रहीं कि इसमें कहा गया कि भारत विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ेगा. विदेशी दौर के संबंध में मोदी का यह कहना काफी अहम रहा कि इसलिए विश्व के साथ हमारे संबंध जीवंत होने चाहिए. औपचारिक संबंधों से कुछ नहीं मिलता है. चार देशों से संबंध रखकर कोई भी देश चल नहीं सकता है. आज सभी देशों से संबंध होने चाहिए, फिर वह छोटा देश ही क्यों न हो. दोनों देशों के बीच दस समझौते भी हुए. भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय एपीएमेट्स के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और को-ऑपरेशन पर ज्वाइंट डिक्लरेशन जारी किया. दोनों देशों ने डिफेंस, साइबर सिक््योरिटी और सिविलियन मामलों में एपीएमेट किए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

## लाशों की पलश करने वाला दरिंदग डेनिस



डेनिस एंड्रयू निल्सन का जन्म 23 नवंबर, 1945 को फ्रेजरबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ. कौन कह सकता था कि मासूम सा दिखने वाला डेनिस आगे चलकर मुसवेल् हिल खूनी और काइनडली खूनी के नाम से कुख्यात होगा. एक ऐसा ब्रिटिश सीरियल किलर, जिसने लंदन में रहकर सन् 1978 से लेकर सन् 1983 के दौरान 15 नौजवानों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया. डेनिस का बचपन शुरू से ही आम बच्चों के बचपन की तरह नहीं गुजरा. डेनिस की मां स्कॉटलैंड और पिता नॉर्वे के थे. पिता के शराब पीने की आदतों की वजह से डेनिस के माता-पिता का तलाक हो गया. जब डेनिस महज चार साल का था, तब उसकी मां ने किसी दूसरे से शादी कर ली और डेनिस को उसके नाना-नानी के पास रहने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ साल बाद डेनिस अपनी मां के साथ ही रहने लगा. डेनिस को बचपन से ही अपने दादा से बहुत लगाव था, लेकिन दादा की मौत के बाद और बार-बार मां और सौतेले पिता द्वारा देह ही अशुद्धियों पर उपदेश सुनने से डेनिस की मानसिकता पर गहरा असर पड़ा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खतरनाक होने लगी. वक्त बीता और डेनिस ब्रिटिश सेना में बतौर कुक काम करने लगा. उसने ऐडन, साइप्रस और बर्लिन में काम किया. उसके बाद सन् 1972 में सेना की नौकरी छोड़कर उसने पुलिस ज्वाइन कर लिया. सन् 1970 के दौर में सिविल नौकर बनकर जॉब सेंटर में काम किया और इसी बीच डेनिस समलैंगिकों से रिश्ते बनाने लगा, लेकिन लोगों द्वारा छोड़ देने, अकेलेपन और समलैंगिक प्रवृत्ति होने की वजह से डेनिस की मानसिकता भयानक रूप लेने लगी. इसी भयानक दरिंदगी के चलते डेनिस छात्राओं और बेघर आदमियों से मिलता और किसी बहाने उन्हें बहला-फुसलाकर अपने घर लाता और रात में उनके साथ दुष्कर्म करके उनका बेरहमी से गला घोट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता. डेनिस की दरिंदगी इतनी बढ़ गई थी कि वह शवों को कसाई की तरह काटकर अपने घर के बगीचे में जला देता. सन् 1981 में डेनिस ने अपना घर निचली मंजिल से ऊपर के प्लेट में शिफ्ट कर लिया. इस दौरान हत्याओं का दौर चलता रहा, लेकिन डेनिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि शवों को कहा ठिकाना लगाया जाए. इस बीच घर पर पड़े शवों की बदबू पड़ोसियों को आने लगी थी. डेनिस को डर था कि कहीं उसका असली चेहरा लोगों के सामने न आ जाए और इसी डर से वह लाशों के छोटे-छोटे टुकड़े कर शौचालय के कंमोड में पलश करके लाशों को ठिकाने लगाने लगा. कुछ महीने डेनिस का आतंक यू ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सीवेज पाइप ब्लॉक हो जाने की वजह से सिवेज कर्मचारियों को बुलाया गया. जब सिवेज पाइप की सफाई की गई तो भारी मात्रा में मांस के टुकड़े मिले. संदेह होने पर सिवेज कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाया. छानबीन के चलते सन् 1983 में कई लोगों की हत्याओं के आरोप में डेनिस को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद डेनिस का खूंखार चेहरा लोगों के सामने आया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान डेनिस के घर की तलाशी ली गई और तलाशी में डेनिस की अलमारी से तीन आदमियों के सिर मिले. 13 लाशें भी डेनिस के पुराने घर से मिलीं. डेनिस पर 15 लोगों की हत्याओं के आरोप साबित होने के बाद 4 नवंबर, 1983 को उसे उग्रकैद की सजा सुना दी गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबरें

## ओबामा ने रूस से मांगी मदद



स्लामिक स्टेट (आईएस) का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है. आईएस के खात्मे के लिए उसने अपने विरोधी देश रूस से मदद मांगी है. 10वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान एशियन लीडर्स से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यूएस और उसके साथी देश आईएस के खिलाफ नरमी नहीं बरतेंगे. उन्होंने कहा कि हम आतंकियों के लीडर्स को टारगेट कर गुप की फाइनेंसिंग सोर्स को खत्म करेंगे. हालांकि, ओबामा ने यह भी कहा है कि मांसको का पूरा फोकस सीरियल प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट करने पर है. उन्होंने रूस से अपनी नीति में बदलाव करते हुए असद को सपोर्ट न करने की भी अपील की है. ओबामा ने कहा कि हम आईएस को खत्म कर देंगे और उसके कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे. उनके लीडर्स को टारगेट कर उनके नेटवर्क और सप्लाय लाइन को नेस्तनाबूत कर देंगे. ओबामा ने कहा कि अगर रूस आईएस के खिलाफ कार्रवाई में आगे आएगा, तब यह काफी मददगार साबित होगा. हालांकि, ओबामा ने उम्मीद जताई है कि मांसको असद को हटाने लिए राजी हो जाएगा. सीएनएन, रॉयटर्स और गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिया का सिविल वॉर अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है. दरअसल, दुनिया के दो सुपरपावर अमेरिका और रूस सीरिया के बहाने पाँचवीं वॉर में लगे हैं. अमेरिका और कई पश्चिमी देश सीरिया के प्रेसिडेंट के विरोधी हैं. वे उन्हें सत्ता से बेदखल कर सरकार में अपने मोहरे बैठाना चाहते हैं. अमेरिका पर आरोप है कि वह असद के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देकर मदद करता है. ऐसे में, रूस अगर असद की मदद करता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि आईएस के खात्मे के लिए रूस अमेरिका की मदद करेगा या नहीं. ■

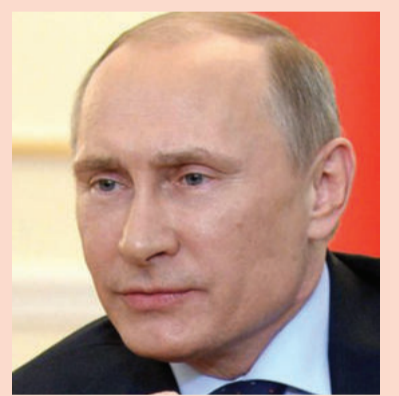
## आखिर पाकिस्तान बेचैन क्यों है



सन् 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के लिए बांग्लादेश में दो शीर्ष विपक्षी नेताओं को फांसी दिए जाने पर पाकिस्तान ने गहरी चिंता और आक्रोश प्रकट किया है. हाल ही में विदेश विभाग ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं सलाउद्दीन कादिर चौधरी और अली अहसान मुजाहिद को फांसी दिए जाने पर एक बयान भी जारी किया है, जिनकी दया याचिका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद ने अस्वीकार कर दी है. विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हम दुर्भाग्यपूर्ण फांसी पर गहरी चिंता और आक्रोश जताते हैं. फिलहाल तो इस घटनाक्रम को लेकर

## तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध

रूस तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. तुर्की ने रूसी विमान गिरा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. टीवी पर दिए गए एक बयान में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवदेव ने कहा है कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साझा निवेश की योजनाओं को भी बंद किया जा सकता है. मेदवदेव ने कहा कि रूस में तुर्की के आर्थिक हितों को सीमित करना या रोक लगाना और सामानों की सप्लाय रोकने जैसे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल है. उन्होंने कहा कि निवेश योजनाओं के साथ भी इसी तरह के नियम लागू होंगे. इन पर तुर्की के साथ सहयोग उसके साथ उच्च स्तर के भरोसे के आधार पर तय होगा. रूस व्यापार के क्षेत्र में तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वहीं तुर्की रूसी पर्यटकों में सबसे लोकप्रिय विदेशी पर्यटक स्थल है. रूस का आरोप है कि तुर्की ने बिना किसी चेतावनी के रूसी विमान को गिरा दिया. दूसरी तरफ तुर्की का दावा है कि रूसी विमान ने चेतावनी के बावजूद तुर्की की वायु सीमा का उल्लंघन किया. तुर्की ने माफी मांगने की रूस की मांग को खारिज कर दिया है. ■









मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में ब्रिटिश प्रशासन का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक आदर्श स्थल है। मुन्नार के आसपास कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जो मनमोहक हिल स्टेशन का आनन्द लेने के लिए यात्रियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।



## खाना पीना

### सर्दियों में बनाएं स्वादिष्ट सत्तू का पराठा

**बि**हार में खूब पसंद किए जाते हैं सत्तू के पराठे, खाने में इनका स्वाद एकदम अलग और स्वादिष्ट होता है तो आप भी बनाकर खाएं बिहार की ये पसंदीदा डिश।

#### आवश्यक सामग्री

- 2 कप सत्तू
- कढ़कस की हुई 5 से 6 लहसुन की कलियां
- बारीक कटे 2 प्याज
- कढ़कस की हुई एक इंच अदरक
- बारीक कटी 3 हरी मिर्च
- 2 चम्मच नींबू का रस
- आधी चम्मच अजवायन
- आम के अचार के 2 टुकड़े पिसे हुए या अमचूर पाउडर



बारीक कटा हरा धनिया  
स्वादानुसार नमक  
तेल

#### आटा गुंदने के लिए सामग्री

- 3 कप गेहूं का आटा
- 2 चम्मच घी
- आधा चम्मच नमक
- विधि**
- स्टफिंग तैयार करने के लिए**
- सत्तू में लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, नींबू का रस, अजवायन, आम का अचार, हरा धनिया, नमक और एक से 2 चम्मच पानी डालकर मिलाएं।
- एक बर्तन में गेहूं का आटा छानकर इसमें घी और आधा चम्मच नमक मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी डालकर नर्म आटा गुंदें।
- आटे की लोई बनाकर उसे पूरी के शेप में बेलें। इसमें सत्तू का मसाला भरकर (स्टफिंग) रखकर पूरी को चारों तरफ से मोड़कर बंद करके दबा दें।
- फिर भरी हुई परियों को बेलकर गोल पराठे बना लें।
- तवा को गर्म करें और उस पर तेल डालकर मध्यम आंच पर पराठा सेंक लें। दोनों तरफ से सुनहरा या ब्राउन होने तक सेंकें।
- सत्तू के पराठे तैयार हैं। इसे चटनी या दही के साथ परोसें।

## फैशन



कोलकाता में मीडियाकॉम मोबाइल की लॉन्चिंग के दौरान मोबाइल का प्रदर्शन करतीं मॉडल्स।

## विंडोज 10 पर चलेगा लुमिया 950 और 950 एक्सएल

**मा**इक्रोसॉफ्ट के नए विंडोज स्मार्टफोन लुमिया 950 और 950 एक्सएल को कंपनी भारत में लॉन्च कर सकती है। यह पहला एकमात्र स्मार्टफोन होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 वर्जन पर चलेगा। लुमिया 950 में 5.2 इंच क्यूएचडी डिस्प्ले होगा, जबकि लुमिया 950 एक्सएल में 5.7 इंच का क्यूएचडी डिस्प्ले होगा। दोनों ही स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कार्ल जेस ऑप्टिक से लैस होगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन में 32 जीबी मेमोरी है, जिसे कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही डिवाइस विंडोज 10 पर काम करेंगे। स्मार्टफोन में 64 बिट हेक्सा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 प्रोसेसर और साथ ही फोन में 3 जीबी रैम होगी। डिवाइस में 21 मेगापिक्सल का प्योरव्यू रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा, 32 जीबी की इनबिल्ट स्टोरेज (माइक्रोएसडी कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद) और 3000 एमएच बैटरी है।



feedback@chauthiduniya.com

## करियर

### मोबाइल गेमिंग में है शानदार करियर

**मो**बाइल गेम को लेकर लोगों के बीच क्रेज टाइम के साथ बढ़ गया है। अगर जॉब के लिहाज से देखें तो इस सेक्टर में जॉब ऑप्शंस की संभावनाएं हैं। आज के हाईटेक वर्ल्ड में बच्चों के साथ-साथ युवा भी हाईटेक गेम्स के दीवाने होने लगे हैं। तभी तो उन्हें अब आउटडोर गेम कम और इंडोर गेम ज्यादा पसंद आने लगा है। यही वजह है कि इंडोर गेम्स यानी वीडियो, कम्प्यूटर और मोबाइल गेम्स का बाजार कई गुना बढ़ गया है। जिस रफ्तार से यह सेक्टर बढ़ रहा है, उससे गेम डेवलपर्स की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मोबाइल गेम्स के फिल्ड में आप गेम डेवलपर, कम्प्यूटर गेम प्रोड्यूसर, गेम डिजाइनर, एनिमेटर, ऑडियो प्रोग्रामर और ग्राफिक प्रोग्रामर बन कर अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं।

#### रोजगार की संभावनाएं :

इस समय रोजगार के लिहाज से यह सेक्टर एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है, क्योंकि कई गेमिंग कंपनियां भारत में अपना सेटअप तैयार करवा रही हैं, लेकिन अच्छे गेम डेवलपर्स की काफी कमी महसूस की जा रही है। इस क्षेत्र में जावा, सी, सी प्लस प्लस, 2डी गेम डेवलपर्स, 3डी डेवलपमेंट के जानकारों के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इस फिल्ड में कई तरह से काम किया जा सकता है।

#### सैलरी पैकेज :

देश में गेमिंग की दुनिया में 2डी और 3डी डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की मांग है। इस हाईटेक गेम वर्ल्ड में शुरुआती दौर में ही आपकी सैलरी 2 लाख रुपये सालाना हो सकती है।

#### टॉप गेम डेवलपर्स :

डिजिटल चॉकोलेट, बंगलुरु  
इंडिया गेम्स, मुंबई  
जंप गेम्स, मुंबई



## शैर-सपाला

### अनोखा पर्यटन स्थल है मुन्नार

**मु**न्नार का केरल में पर्यटन स्थल के तौर पर काफी महत्व है। मुन्नार तीन पर्वतों की श्रृंखला है। मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में दक्षिण भारत के पूर्व ब्रिटिश प्रशासन का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक आदर्श स्थल है। मनमोहक हिल स्टेशन के कारण इस स्थान की छवि देखते ही बनती है। अगर आपको असीम आनंद चाहिए तो मुन्नार आना न भूलें। और क्या देखने के लिए है मुन्नार में, आइए आपको बताते हैं:

#### राष्ट्रीय उद्यान

इचिकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार और उसके आसपास के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह मुन्नार से लगभग 14 किमी दूर है और लुमप्राय

प्राणी-नीलगिरी टार के लिए जाना जाता है। लगभग 96 वर्गकिमी में फैला यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है। यह ट्रैकिंग के लिए भी सर्वोत्तम स्थान है। यह उद्यान चाय के बगान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर थुंध की चादर का एक विस्तृत नजारा पेश करता है। नीलकुर्रिजी के फूल यहां के वातावरण को और भी मनोरम कर देता है। नीलकुर्रिजी नीले रंग का फूल होता है। जब यह खिलता है तो पहाड़ों की ढाल नीली चादर से ढक जाती है, तब यह उद्यान ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए खूबसूरत स्थल बन जाता है।

#### माट्टूपेट्टी

मुन्नार शहर से लगभग 12 किमी दूर स्थित दूसरा दिलचस्प स्थान है माट्टूपेट्टी। माट्टूपेट्टी अपने स्टारज मेसनरी बांध और खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्वतों के लिए आसपास के पहाड़ों और

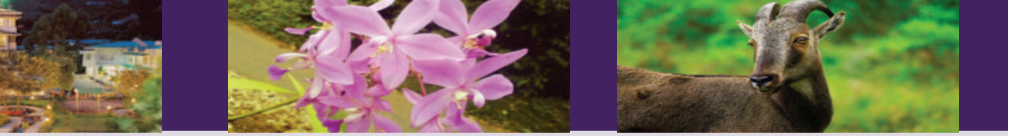
भू-दृश्यों का मजा लेते हुए आनन्ददायक नौकाविहार की सुविधा है। यहां आप गायां की अधिक दूध देने वाली नस्लें देख सकते हैं। हरे-भरे चाय के बगान, ऊंचे-नीचे घास के मैदान और शोला वन के साथ-साथ माट्टूपेट्टी ट्रैकिंग के लिए भी आदर्श स्थल है और यहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी बसेरा है।

#### पल्लिवासल

पल्लिवासल मुन्नार के चितिरपुरम से लगभग 12 किमी दूर स्थित है। यह स्थल व्यापक प्राकृतिक सुन्दरताओं से भरा पड़ा है और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्थल है।

#### चिन्नकनाल

चिन्नकनाल मुन्नार शहर के निकट स्थित है। यहां के झरनें, जिसे आमतौर पर पावर हाउस वाटरफॉल कहा जाता है, खड़ी चट्टान पर समुद्र तल से 2000



मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। यह स्थल पश्चिमी घाट की पर्वत-श्रेणियों के प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध हैं।

#### टॉप स्टेशन

मुन्नार-कोडेकनाल सड़क पर स्थित यह सबसे ऊंचा स्थान है। टॉप स्टेशन देखने आने वाले पर्यटक मुन्नार को अपना पड़ाव बनाते हैं और इस टॉप स्टेशन से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के विहंगम दृश्यों का आनन्द लेते हैं। मुन्नार में, यहां से विस्तृत क्षेत्र में

नीलकुर्रिजी के खिले हुए फूलों को देखने के लिए भी यह एक उपयुक्त स्थान है।

#### कैसे जाएं:

मुन्नार जाने के लिए सड़क और हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध है।

चौथी दुनिया व्यूरो

feedback@chauthiduniya.com



## अब सुपरगर्ल का किरदार निभाना चाहती हैं सनी लियोनी

**पाँ** न फिल्मों से बॉलीवुड का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी अब सुपरगर्ल का किरदार निभाना चाहती हैं। पिछले कई सालों में बॉलीवुड में सुपरहीरो की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है। सनी अपनी आने वाली होम प्रोडक्शन फिल्म में सुपरगर्ल का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। सनी ने कहा कि वह और उनके पति वेब डेनियल सुपरगर्ल का किरदार तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही सनी ने कहा कि वह अलग तरह की चीजें करने में विश्वास रखती हैं। यह फिल्म सनी लियोनी की होम प्रोडक्शन फिल्म होगी। फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेता रितिक रोशन क्रिश सीरीज में सुपरहीरो का किरदार निभा चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ भी उनकी आगामी फिल्म में सुपरहीरो के किरदार में नजर आएंगे।

## प्रीति जिंटा बनेंगी दुल्हन

एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेने, प्रीति के ब्वॉयफ्रेंड नहीं हैं बल्कि करीबी दोस्त हैं। हालांकि प्रीति अपने भाई और उसके परिवार से मिलने नियमित तौर पर अमेरिका जाती रहती हैं। इसके अलावा उनके कई करीबी दोस्त भी अमेरिका में रहते हैं।

**बाँ** लीवुड की चुलबुली अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अंततः शादी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीति अगले साल जनवरी तक अपने अमेरिकी ब्वॉयफ्रेंड जेने गुडेनसेफ से शादी कर सकती हैं। शादी के लिए प्रीति अमेरिका जाएंगी। इस विवाह समारोह में प्रीति का परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेने, प्रीति के ब्वॉयफ्रेंड नहीं हैं बल्कि करीबी दोस्त हैं। हालांकि प्रीति अपने भाई और उसके परिवार से मिलने नियमित तौर पर अमेरिका जाती रहती हैं। इसके अलावा उनके कई करीबी दोस्त भी अमेरिका में रहते हैं। हालांकि प्रीति ने शादी की खबरों को अफवाह बताया है। इससे पहले प्रीति का नेस वाडिया के साथ संबंध रहे थे। इनसे ब्रेकअप के बाद उनका नाम युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मिलर से भी जुड़ चुका है।



## तमाशा आत्मकथा नहीं है इम्तियाज अली

**नि** देशक इम्तियाज अली ने बताया कि उनकी फिल्म तमाशा में उनकी जिंदगी के कुछ पल हैं लेकिन, यह कोई आत्मकथा नहीं है। फिल्म की कहानी के बारे में इम्तियाज ने कहा कि फिल्म तमाशा ऐसे प्यार की कहानी है, जो सामान्य लोगों के लिए असाधारण है, जिससे वह कलाकार और आम आदमी बनते हैं। यह इस तरह की कहानी है, जिसमें आप समझेंगे कि जिंदगी में महिलाएं क्यों जरूरी हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको पहचान दिलाएगी। इम्तियाज अली अपनी पत्नी से कुछ साल पहले अलग हुए हैं, उनका मानना है कि व्यक्तिगत जीवन और विचार आपको कहानी सुझाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी निजी जिंदगी पर आधारित फिल्म पर कहानी गढ़ें। उन्होंने बताया, फिल्म तमाशा में मेरी जिंदगी के कुछ पल हैं जिन्हें आप देखेंगे, लेकिन यह आत्मकथा नहीं है। अली ने कहा, मुझे तमाशा शीर्षक पहली बार में पसंद आया। तमाशा का अर्थ दृश्य जिसे आप देखेंगे और आनंद लेंगे। इम्तियाज ने इस फिल्म में अपने अंग्रेजी शीर्षक की प्रवृत्ति तोड़ी है, इससे पहले अपनी फिल्मों को जब वी मेट, रॉकस्टार और हाइवे जैसे नाम दिए हैं।

## सेंसर बोर्ड पर आमिर ने उठाए सवाल



**जे** मस बांड की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची के बारे में आमिर ने कहा है कि हाल-फिलहाल में सेंसर बोर्ड थोड़ा आक्रामक हुआ है। उनका मानना है कि यदि फिल्म को वयस्क प्रमाणपत्र (एडल्ट सर्टिफिकेट) मिल गया है, तो उसमें आप लगभग सबकुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी वयस्क तय कर सकता है कि उसे फिल्म देखनी है या नहीं। प्रमाणपत्र के बाद सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। प्रमाणपत्र की हमारी समझ यही है। आमिर खान ने वर्तमान सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि सेंसर बोर्ड का असली काम इस बात का प्रमाण देना है कि किस आयु वर्ग के लोग कौन सी फिल्म देखें। आमिर ने मजाक के लहजे में कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का किस सीन सेंसर नहीं किया गया था। दरअसल सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्पेक्टर के किसिंग सीन्स पर कैंची चलाते हुए उसकी अवधि कम कर दी है। इस वजह से सेंसर बोर्ड को सोशल मीडिया पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

## हिंदी फिल्मों का अनमोल रत्न अमोल पालेकर

महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी तीन बहनें थीं। उनके परिवार का फिल्मों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल-कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक में भी काम नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थीं। ग्रैजुएशन के बाद अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में आठ साल तक नौकरी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती तीन फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थीं, तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था।



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

**अ**मोल पालेकर हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने आर्ट और व्यावसायिक सिनेमा के बीच की खींचतान के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 24 नवंबर को वह 71 साल के हो गए। फिलहाल वह एक पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पोस्टक ग्रेजुएशन करने के बाद करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। वह अक्सर कहते रहे हैं, मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना लेकिन दुर्घटनावश एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बना और अपनी पसंद से डायरेक्टर बना। 1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान थी। उस दौर में वह काफी सोच-समझ कर फिल्में करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दस में से नौ फिल्में रिजेक्ट कर देते थे। सत्तर के दशक में बासु चटर्जी-अमोल पालेकर की जोड़ी मनमोहन देसाई-अमिताभ बच्चन जैसी थी। इसके अलावा उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। आकृत, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, दायरा, कैरी, पहली आदि फिल्मों और कच्ची धूप, नकाब, मृगनयनी जैसे टीवी सीरियलों के निर्देशन में अपना कमाल दिखाया।

महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी तीन बहनें थीं। उनके परिवार का फिल्मों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल-कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक में भी काम नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थीं। ग्रैजुएशन के बाद अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में आठ साल तक नौकरी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती तीन फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थीं, तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था।

एक्टिंग से उनका रिश्ता कुछ इस तरह जुड़ा, उनकी गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्पी रखती थीं। जब वह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती थीं तब अमोल वहां उनका इंतजार करते थे। इसी दौरान एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नज़र उनपर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांताता! कोर्ट चालू आहें में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद

सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है, तो उन्हें एक्टिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए, अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को प्रशिक्षित किया। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर शुरू से तड़क-भड़क से दूर रहने वाले हैं। वह ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी थीं। अमोल ने दो शायदियां कीं।

फिल्मों में अभिनय करने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशक के रूप में स्थाई पहचान बना चुके थे। सत्यदेव दुबे के साथ शुरुआती दौर में काम करने के बाद साल 1972 में उन्होंने अनिकेत नाम से अपने थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। बासु

1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान थी। उस दौर में वह काफी सोच-समझ कर फिल्में करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दस में से नौ फिल्में रिजेक्ट कर देते थे। सत्तर के दशक में बासु चटर्जी-अमोल पालेकर की जोड़ी मनमोहन देसाई-अमिताभ बच्चन जैसी थी। इसके अलावा उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई।

चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य उनके नाटक देखने आया करते थे। उन्होंने सन 1974 में बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म सफल हुई। उन्होंने एक्टर के रूप में चितचोर, घरींदा, मेरी बीवी की शादी, बातों-बातों में, गोलमाल, नरम-गरम, श्रीमान-श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्मों दीं। वे ज्यादातर फिल्मों में मध्यवर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते दिखे। उनकी हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। उन्हें खुशी है कि वे अपने करियर में फिल्म जगत के श्रेष्ठ निर्देशकों और श्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ काम कर सके सन 1981 में मराठी फिल्म आक्रित से अमोल ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। अब तक वे कुल दस हिंदी-मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली हिंदी फिल्म पहली को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने निर्देशक के रूप में मनमाफिक फिल्म बनाई। बहुत जल्द फिल्म दुमकटा रिलीज होगी। उनकी यह फिल्म बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित होगी।

## मेरी इजाजत के बगैर रणबीर नहीं कर सकते शादी: दीपिका

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तमाशा रणबीर और दीपिका की एक-साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों फिल्म बचना ऐ हसीनों और ये जवानी है दीवानी में एक-साथ दिखाई दिए हैं। दोनों के बीच की केमेस्ट्री को भी दर्शकों ने पसंद किया है।

**अ**भिनेत्री दीपिका पादुकोण का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना अभिनेता रणबीर कपूर शादी नहीं कर सकते हैं। जब उनसे रणबीर और कैटरिना की शादी से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो इसके उत्तर में दीपिका ने यह बात कही। इस प्रकार रणबीर और दीपिका अनेक सालों तक रिश्तों में थे और आज भी दोनों के मध्य संबंध काफी सौहार्दपूर्ण हैं। दीपिका ने कहा कि रणबीर मेरी इजाजत के बिना शादी नहीं कर सकते। रणबीर ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा शादी के रिश्ते में पूर्ण भरोसा है। जब मैं शादी करूंगा तो पूरी दुनिया को इसके संबंध में अवश्य ही जानकारी दूंगा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तमाशा रणबीर और दीपिका की एक-साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों फिल्म बचना ऐ हसीनों और ये जवानी है दीवानी में एक-साथ दिखाई दिए हैं। दोनों के बीच की केमेस्ट्री भी दर्शकों ने पसंद किया है, हाल ही में हुए एक सर्वे में दोनों की जोड़ी शाहरुख और काजोल की जोड़ी से आगे नज़र आई थी।



# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

## बिहार-झारखंड

07 दिसंबर-13 दिसंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार का पहला आधुनिक तकनीक से निर्मित सरिया

**PRIME GOLD**

TMT, COIL & ANGLE PATTI  
PURE STEEL

PLATINUM ISPAT INDUSTRIES PVT. LTD.  
DIDARGANJ PATNA CITY  
Mob : 9470036601, 9334317304



The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

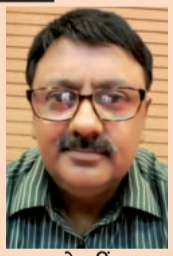
Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org



# आखिर कौन है हार का जिम्मेदार

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. चुनाव में एनडीए की हुई करारी हार जगजाहिर है. इस हार से जमीनी कार्यकर्ता व नेता हताश हैं लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर इस बात का शायद कोई असर नहीं पड़ रहा है. एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के नेता इस हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ कर अपना सिर बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं. एनडीए के नेताओं के बीच चलती कशमकश पर पढ़िए हमारी यह स्टोरी...



सरोज सिंह

**बि**हार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के घटक दलों में एक अजीब खामोशी है. झटका ऐसा है कि संभलने में चकत्त लोग लेकिन लगभग सभी पार्टियों के दफ्तरों में इस बात की चर्चा दबी जुबान से जरूर है कि आखिर कौन है इस हार का जिम्मेदार? कोई भी नेता अपने ऊपर हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. हां, जीत की स्थिति में ऐसे नेता मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री तक बनने का दावा ठोंके हुए थे, लेकिन जैसे ही बाजी पलटी बड़े नेताओं ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया. कुछ औपचारिक बयान देकर हार से पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई पर न ही किसी ने अपने हार से इस्तीफा दिया और न ही किसी नेता को साइडलाइन किया गया. ऐसे में छोटे नेता और कार्यकर्ता जगह-जगह यह सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए के बड़े नेताओं को अब हो क्या गया है? चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे कर हेलिकॉप्टर पर उड़ान भरने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? आखिर किसी न किसी को इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका दंड भुगतना होगा या फिर टालमटोल कर सारी बातें रफा-दफा कर दी जाएंगी.

बात प्रदेश भाजपा की करें तो यहां मोटे तौर पर सारी कवायद मंगल पांडेय, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और संघ की ओर से नागेंद्र जी के आसपास घूमती रही. भाजपा के अंदर की यह व्यवस्था कई नेताओं को खराब भी लगती थी कि चुनाव हारने के बाद ये नेता हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने-अपने मौजूदा पदों से इस्तीफे की पेशकश करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. हद तो यह है कि ये सभी नेता एक बार फिर भाजपा पर अपना दबदबा बरकरार रखने के जुगाड़ में लग गए हैं. हार के

कारणों पर विचार के लिए हुए मंथन में यह आम राय बनाने का प्रयास हुआ कि टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा व जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर बाहरी लोगों को टिकट देने का कोई लाभ नहीं हुआ. भाजपा से जुड़े एक मंच के पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं की बेहिसाब दौरों व सभा का खराब प्रभाव पड़ा. उम्मीदवार लोग सभा को सफल बनाने में ही रह गए और जनता से सही संपर्क नहीं कर पाए. इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को भी स्थानीय कार्यकर्ताओं की तुलना में ज्यादा तरजीह दी गई. इसका कुप्रभाव यह हुआ कि भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन से चुनाव में नहीं लगे. जो लोग टिकट न मिलने से दुखी और नाराज थे उन्हें मनाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया. केवल सतही तौर पर खाना पूर्ति की गई. एक अनुमान के अनुसार इससे भाजपा को कम से कम डेढ़ दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बैठक में कहा कि हमलोग इतने फील गुड में थे कि मतदाता जागरण और वोट पच्ची देकर अपने परंपरागत तरीके को भी भूला दिया गया. दिल्ली के नेताओं के करीबी माने जाने वाले प्रदेश के एक नेता कई क्षेत्रों में अपना एजेंडा चला रहे थे और केंद्रीय नेताओं को गलत फीडबैक दे रहे थे. मंथन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई पर किसी नेता ने अपने माथे पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली और न ही इस्तीफे की पेशकश की. लोजपा का हाल सबसे जुदा है.

चुनाव के दौरान तो ऐसा लगता था कि सांसद चिराग पासवान एक ऐसा जादू है जो जिस इलाके में चला गया वहां के उम्मीदवार की जीत तय है. टिकट वितरण से लेकर मतदान के दिन तक चिराग पासवान अपनी बचकानी मनमानी करते रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि लोजपा 43 में से केवल दो सीट जीत पाई. इनमें में भी जो दो लोग जीते हैं वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जीते हैं, उसमें पार्टी और चिराग पासवान का कोई योगदान नहीं है. लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि अभी तक पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष और सांसद चिराग

पासवान ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश नहीं की. टिकटों के वितरण के बातचीत में चिराग के अंडियल रवैये से भाजपा के कई नेता काफी नाराज थे पर गठबंधन धर्म और रामविलास पासवान की इमेज को लेकर वे शांत रहे, लेकिन अब चिराग का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. अंदरखाने सबसे अधिक विरोध तो उनकी पार्टी के भीतर ही हो रहा है. हाई

चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे कर हेलिकॉप्टर पर उड़ान भरने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? आखिर किसी न किसी को इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका दंड भुगतना होगा या फिर टालमटोल कर सारी बातें रफा-दफा कर दी जाएंगी. बात प्रदेश भाजपा की करें तो यहां मोटे तौर पर सारी कवायद मंगल पांडेय, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और संघ की ओर से नागेंद्र जी के आसपास घूमती रही.

फाई स्टाइल में पार्टी चलाने का क्या नतीजा होता है यह बिहार के चुनाव में साबित हो गया. लोजपा के कई नेता कह रहे हैं कि अगर रामविलास पासवान पुत्र मोह में फंसे रहे तो पार्टी का सत्यानाश तय है. लोकसभा में मोदी लहर के कारण मिली जीत का सेहरा रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग के सिर बांधते रहे अब अगर पार्टी की करारी हार हुई है तो पता नहीं उनकी जुबां पर क्यों ताला लगा हुआ है? प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस खुद चुनाव



हार गए इसलिए वह कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हैं. पार्टी को नए सिरे से अगली लड़ाई के लिए खड़ा करना उनके लिए कड़ी चुनौती है. लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर चिराग पर लगाम नहीं लगाया तो फिर पशुपति कुमार पारस भी कुछ नहीं कर पाएंगे. बिहार के बारे में चिराग की कम समझ लोजपा के लिए खतरनाक साबित हो रही है. बिना मतलब के टांग अड़ाने की चिराग की आदत पार्टी को गर्त पर लाकर खड़ा कर चुकी है. देखना है रामविलास पासवान इस संकट से कैसे निपटते हैं? जहां तक बात रालोसपा की है तो यह माना ही जा रहा था कि उसके दो बड़े नेताओं उषेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार की आपसी खींचतान से पार्टी को नुकसान होगा ही होगा. जब चुनाव के नतीजे आए तो यह बात साबित भी हो गई. दूसरे दलों की तरह इस पार्टी के भी दोनों बड़े नेताओं ने हार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और न ही अपने पद से इस्तीफे की ही पेशकश की. पार्टी के अंदर बात चल रही है कि रालोसपा पूरे बिहार की नहीं बल्कि एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई थी और

इसी वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं. पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हमें अपना चरित्र बदलना होगा. किसी एक जाति या वर्ग को लेकर हमलोग बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं. जीतनराम मांडी की पार्टी हम में भी मंथन जारी है पर कोई भी हार की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेने को तैयार नहीं है. हम के सारे बड़े नेता अपनी-अपनी सीट बचाने में लगे थे और सामूहिक तौर पर कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा था. नतीजा यह हुआ कि सारे बड़े नेता और इनके रिश्तेदार तो हार ही गए पार्टी भी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई. अकेले जीतनराम मांडी ने हार की समीक्षा के लिए एनडीए की एक बैठक बुलाने की मांग की है पर उनकी मांग पर किसी भी दल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है. देखा जाए तो हार के बाद एनडीए के दल हताश हैं क्योंकि एक सूत्र में बंधने की इनकी आधे मन से की गई कवायद पूरी तरह फेल हो गई है. पहले तो सभी दलों को अपने ही दल में सामने आ गई चुनौतियों से निपटना है एनडीए को एक रखने की बात तो दूर की कौड़ी है.





# चौथी दुनिया

07 दिसंबर-13 दिसंबर, 2015

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

## उत्तर प्रदेश—उत्तराखंड

### सैफई में मना मुलायम का भव्य जन्मदिवस समारोह, प्रदेश भर में बांटे गए लड्डू



# अमर पर मुलायमियत से बेकायद आजम



प्रभात रंजन दीन

मुलायम सिंह यादव के तब के जन्मदिन और मुलायम सिंह यादव के अब के जन्मदिन में रेखांकित करने वाला फर्क है। पिछले साल जब आजम खान ने समाजवाद के पुरोधा को ब्रिटिश सामंती औपनिवेशिक विचार-बगधी पर बैठा कर रामपुर की सड़कों पर विचरण करवाया था, तब समाजवाद अपनी सड़क से भटका हुआ उद्धोषित हुआ था। इस साल जब जन्मदिवस समारोह में आजम खान मुख्य भूमिका और सटीक समय, दोनों से नदारद थे, तो समाजवाद पिछली गलतियों पर प्रायश्चित्त करता हुआ प्रतीत हुआ। पिछले साल मुलायम के जन्मदिन समारोह में अमर सिंह नहीं दिखे, तो समाजवादी पार्टी की नई संभावनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इस साल जन्मदिवस

समारोह में अमर सिंह जब मुलायम को केक खिला रहे थे और मुलायम भी बड़े प्यार से अमर के मुंह में केक टूस रहे थे, तो विशाल शामियाने में समाजवादी पार्टी की नई संभावनाएं एआर रहमान के गाने जय-हो की तरह गूंज रही थीं। पिछले साल तक आजम-प्रभाव में कोई जयाप्रदा का नाम तक नहीं ले सकता था, इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयाप्रदा से बड़ी अंतरंगता से बतिया रहे थे, तो किसी अनजाने से नयेपन का पुरखता संदेश जनसमूह के बीच जा रहा था। अमर सिंह से परहेज करने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी अमर को स्वीकार करने के भाव में दिखे और अमर को अस्वीकार करने वाले आजम फोटो-फ्रेम में कहीं नहीं दिखे। लिहाजा, मुलायम का इस बार का जन्मोत्सव भविष्य के नए सियासी समीकरणों का भूमिकोत्सव साबित हुआ। अखिलेश यादव ने कहा भी कि वह अपने पिता को उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में 2017 में दोबारा सरकार देना चाहते हैं।

जन्मदिवस के मौके पर आयोजित भव्य

## 207 फीट उंचा झंडा देकर दिया बर्थ-डे गिफ्ट

लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के मौके पर राज्य सरकार ने 207 फीट उंचे फ्लैग पोल पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर प्रदेश के लोगों को उपहार दिया। इसे मॉन्यूमेंटल फ्लैग का नाम दिया गया। इस मौके पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी समेत कई हस्तियां यहां मौजूद थीं। देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा भी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता में उस देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने हमेशा ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनका अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके। वर्तमान सरकार ने जनेश्वर मिश्र के नाम पर विश्वस्तरीय पार्क विकसित करने का काम शुरू किया था, जो अब साकार रूप ले रहा है। लगभग 376 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क में दुनिया के तमाम मशहूर पार्कों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद मुलायम सिंह यादव को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि नेताजी ने समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए सदैव संघर्ष किया और सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में जीवन की शुरुआत की और समाजवाद में आस्था होने के कारण राजनीति का संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। समाज के गरीबों, मजदूरों, दबे-कुचले वर्गों, अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए उनके मन में अपार स्नेह है। किसानों के वे परम हितैषी हैं। अखिलेश ने सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि विकास ही समाजवादी राजनीति का मूल मंत्र है। अपने पिता के जन्मदिवस पर अखिलेश भावुक भी हुए और कहा कि हम नेताजी के मार्गदर्शन में सपा को चलाएंगे और आम आदमी की लड़ाई जारी रखेंगे। नेताजी खुद मुख्यमंत्री रहे और मुझे भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उनके बिना मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। नेताजी ने जिस भी नेता



(शेष पृष्ठ 20 पर)

समारोह और भारी जनसमूह की मौजूदगी में मुलायम जब अपने 76वें जन्मदिवस का केक काटने स्टेज पर पहुंचे, तो अमर सिंह उनके साथ थे। अमर सिंह ने ही सपा महासचिव रामगोपाल यादव और बाकी लोगों को मंच पर बुलाया। 76 किलो का केक काटने के बाद मुलायम सिंह यादव को केक का पहला टुकड़ा अमर सिंह ने ही खिलाया। इसके बाद मुलायम ने भी केक का दूसरा टुकड़ा अमर सिंह को खिलाया। राजनीति में इस केक के दूसरे टुकड़े के भी कई विश्लेषण हैं। केक काटने के वक्त आजम खान की गैरहाजिरी भी इस समीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। जिस समय मुलायम अपने जन्मदिन का केक काट रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया प्रदा, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, लालू के दामाद तेजप्रताप यादव व मुलायम-परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। केक काटने से पहले मुलायम ने कहा कि समाजवाद का मतलब भूखा नंगा होना नहीं होता, बल्कि समाजवाद का अर्थ सम्पन्नता की ओर बढ़ना होता है। केक काटने की औपचारिकता के बाद जब समारोह शुरू हुआ तब भी मुलायम ने अपने बगल में अमर को ही बैठाया। रामगोपाल, शिवपाल व अन्य नेता बगल की सीटों पर बैठे और अखिलेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग बैठे थे। आजम खान केक काटने के काफी देर बाद आए और थोड़ी देर बाद ही फिर कहीं नहीं दिखे। आजम खान अमर सिंह की मौजूदगी से इतने ज्यादा खफा हुए कि सैफई में होने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

मुलायम के समधी लालू प्रसाद यादव जन्मदिवस समारोह में नहीं पहुंचे। ये बातें पारिवारिक नहीं, राजनीतिक हैं, यह साफ तौर पर साबित हुआ। नीतीश कुमार और लालू के बेटों के शपथ ग्रहण समारोह में न मुलायम गए थे और न ही अखिलेश। सपा की तरफ से कोई प्रतिनिधि नेता भी शपथ ग्रहण में शरीक नहीं हुआ था। लिहाजा, जन्मदिवस में लालू के शरीक नहीं होने को भी उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि मुलायम के पोते और लालू के दामाद तेज प्रताप यादव ने इस पर दूसरी परतें चढ़ाने की काफी कोशिश की। सांसद तेजु ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूरा परिवार काफी थका

(शेष पृष्ठ 20 पर)







सपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने-अपने घरों पर दीप जलाएं और लाइटिंग करें. सैफई महोत्सव के कार्यकारी प्रबंधक वेदव्रत गुप्ता ने बताया कि मुख्य समारोह स्थल एथलेटिक्स स्टेडियम में एक लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था. मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने अपने 300 सदस्यों की टीम के साथ संगीत का जादू बिखेरा. हरिहरन और जावेद अली जैसे मशहूर गायकों ने भी मुलायम के जन्मदिवस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी.

लखनऊ विश्वविद्यालय में मची है अराजकता और अंधेरगर्दी

# नियम और शिक्षा दोनों ही ताक पर

रोहित पांडेय

लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ वित्तीय अनियमितता ही नहीं व्याप्त है, बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की योग्यता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं. विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक भी सेवा दे रहे हैं जिनकी खुद की योग्यता भी पूरी नहीं है. विश्वविद्यालय सहित अन्य स्थानों पर लगभग हर माह शिक्षा की गुणवत्ता पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं. ऐसे गुरुजनों से गुणवत्तापरक शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है! यह शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों को पूरा नहीं करते और अनियमित ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जो एक योग्यताधारी शिक्षक को प्राप्त होती

## विनियमित करने की शर्तें

1. अभ्यर्थी पूर्णतया यूजीसी के नियमों का पालन करता हो.
2. अभ्यर्थी लगातार कार्यरत रहा हो, किसी अन्य संस्थान में न गया हो और अधिक दिनों तक गैरहाजिर न रहा हो.
3. जिस ग्रेड की पोस्ट खाली हो उसी में नियमित कर दिया जाए.

हैं. विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉ. रंजना वैशंपायन नियुक्ति की अर्हता पर खरी नहीं उतरती हैं, जिसके बावजूद उन्हें प्रवक्ता के पद पर 10.06.2004 को नियुक्त कर दिया गया. यही नहीं इनको प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत भी कर दिया गया. डॉ. रंजना वैशंपायन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक हैं. जिसमें इन्हें मात्र 52 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. एक चॉकाने वाला पहलू यह भी सामने आया



## लेकिन प्रावधान रख दिए गए ताक पर

नियुक्ति के समय शर्तों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए लाभ पहुंचाया गया. डॉ. रंजना वैशंपायन कानपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रो. जेबी वैशंपायन की पत्नी हैं जो पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर तैनात रहे थे. विश्वविद्यालय के इस फर्जीवाड़े को जांचने के लिए बनी कमेटी ने मात्र सात शिक्षकों को यूजीसी के नियमों के आधार पर खरा पाया था. शेष कोई भी योग्यता पूरी नहीं रखता था. इस बारे में जब डॉ. रंजना वैशंपायन से बात की गई तो उन्होंने योग्यता संबंधी सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कुछ देर बाद उन्होंने फोन करके बताया कि जो 1991 के पहले एमए कर चुके थे उन्हें पीएचडी में पांच फीसदी अंक की राहत प्रदान की गई थी. जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका. जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की परिनियमावली (1993) अध्यापकों की अर्हता और नियुक्ति के विषय में कहती है कि कला, वाणिज्य और विज्ञान विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक से स्नातकोत्तर होने के साथ-साथ उच्च शैक्षणिक अभिलेख का होना भी जरूरी है. लिहाजा, डॉ. रंजना वैशंपायन का तर्क उचित नहीं है. विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉ. अवधेश यादव (2003 के पीएचडी) इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां न्याय नहीं मिला, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉ. रंजना वैशंपायन का प्रोन्नत करके प्रोफेसर की गरिमामयी कुर्सी पर बैठा दिया. यह आश्चर्यजनक है.

## क्या कहता है अधिनियम

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षक पद के लिए कम से कम संगत विषय में 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और उच्च शैक्षणिक अभिलेख होना अनिवार्य है. जबकि डॉ. रंजना वैशंपायन के शैक्षणिक अभिलेख भी मानक पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि इन्होंने हाईस्कूल में तृतीय श्रेणी व इंटर में द्वितीय श्रेणी स्थापना हासिल किया है. लखनऊ विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार का यह मात्र एक बानगी है इस प्रकार न जाने कितने अयोग्य शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं. विश्वविद्यालय के एक शिक्षक नेता ने बताया कि 2004 में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की मांग पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31-सी में परिवर्तन करके नियमों के तहत उन शिक्षकों को विनियमित करने की घोषणा की थी जो 31 दिसंबर 1997 से 2004 तक अद्यतन शिक्षण कार्य कर रहे थे और यूजीसी के मानकों पर खरे उतरते थे. ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 50 तक थी.

है कि नियुक्ति पत्र जो कि कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, वह कुलसचिव के हस्ताक्षर से न जारी करके कुलसचिव कार्यालय में तैनात किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. सूत्रों कि मानें तो कुलसचिव को फर्जीवाड़े की भनक लग गई तो वे अवकाश पर चले गए. नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन इतना उतावला था कि कुलसचिव व उपकुलसचिव की गैरमौजूदगी में विश्वविद्यालय के एक अवकाशप्राप्त कर्मचारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव से हस्ताक्षर करावा कर डॉ. रंजना वैशंपायन की नियुक्ति कर दी गई.

feedback@chauthiduniya.com

# अमर पर मुलायमियत से बेक़ायदे आजम

पृष्ठ 17 का शेष

हुआ था. इसलिए लालू यादव जन्मदिवस समारोह में नहीं आ सके. इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन मतलब निकालने की प्रक्रिया इन बातों से और गति में रही. मुलायम के जन्मदिवस समारोह ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को खूब नाराज किया. आजम ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे लगा कि आजम खान अपनी मर्जी से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. शीर्ष नेतृत्व के फैसले उन्हें कतई गवारा नहीं. अपने निजी जौहर विश्वविद्यालय में अनुशासन पर बड़ी-बड़ी तकरारें पढ़ने वाले आजम खान अपनी ही पार्टी के अभिभावक के जन्मदिवस को लेकर क्या-क्या कहते हैं, यह सुनें तो आपको सपा नेतृत्व का विश्वास चेहरा सामने नजर आएगा, जो अनुशासनिक कार्रवाई में बड़ों के सामने पंगु और अदनों के आगे तना दिखाई देता है. आजम कहते हैं, सैफई में जो केक काटा गया था, वह असली केक नहीं था. असली केक तो उनके साथ रामपुर में कटा था. केक काटने के वक्त को लेकर भी आजम खान ने गुस्सा जताया और कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है. मैंने नेताजी का जन्मदिन तय समय पर केक काटकर मनाया था. मुलायम के जन्मदिवस समारोह में अमर सिंह के सैफई पहुंचने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परवाह किए बगैर आजम ने कहा, जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट आ ही जाता है. बिहार चुनाव के तूफान के बाद अमर सिंह जैसे कूड़ा-करकट के आगमन पर कही गई आजम की ये बातें प्रदेश के आम नागरिकों और सियासतदार्ताओं को काफी नागवार लगतीं, सपा नेतृत्व पर इन बातों का क्या असर पड़ा, अभी यह समय के पहलू में छिपा है.



## 207 फीट ऊंचा झंडा देकर दिया बर्थ-डे गिफ्ट

पृष्ठ 17 का शेष

को डांटा, उनका जीवन बन गया और वे भाग्यशाली हैं. इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रखर समाजवादी जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क का निर्माण कर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं. यह पार्क अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पार्क के रूप में विकसित हो रहा है और मॉड्युमेंटल फ्लैग लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम और गौरव की भावना जगाएगा. यह ऐसा प्रतीक-चिन्ह है, जिसके सम्मान के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है. हमारा तिहुंगा भारत के मान और सम्मान का प्रतीक है. इस अवसर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मुलायम को इतिहास का निर्माता बताया और कहा कि नई पीढ़ी को मुलायम के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए. कार्यक्रम को महाकवि गोपाल दास नीरज, साहित्यकार उदय प्रताप, बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन, कारागार मंत्री बलवन्त सिंह रामवर्मा, टीने वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले रहमान, इंदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष एनसी बाजपेयी वगैरह ने भी सम्बोधित किया. मुलायम के जन्मदिवस के मौके पर उनके राजनीतिक जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया. फोटो प्रदर्शनी में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की तस्वीरें खास तौर पर लगाई गई थीं. मुख्यमंत्री ने उन तस्वीरों को समाजवाद का इतिहास बताया और कहा कि ये सभी चित्र नेताजी के जीवन और संघर्ष के साथ-साथ वर्तमान सरकार के कार्यकलापों को भी दर्शाते हैं.



## ढाई करोड़ का बना था मंच

मुलायम के जन्मदिवस पर सैफई में ढाई करोड़ का मंच बना था. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता के जन्मदिन को विशेष बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. स्टेडियम में आयोजित हुए भव्य समारोह में शासन के आला अधिकारी भी खास तौर मौजूद थे. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रमुख सचिव अनीता सिंह, प्रदेश के डीजीपी जगमोहन यादव, इटावा के जिलाधिकारी नितिन बंसल, इटावा की एसएसपी मंजिल डैनी समेत तमाम अधिकारी कार्यक्रम में देखे गए. जन्मोत्सव के आयोजन में जिला प्रशासन जी-जान से जुटा रहा. शासन की लगातार निगरानी चलती रही. मुलायम के जन्मदिवस पर पूरे सैफई में प्रायोजित दीपावली मनी. सपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने-अपने घरों पर दीप जलाएं और लाइटिंग करें. सैफई महोत्सव के कार्यकारी प्रबंधक वेदव्रत गुप्ता ने बताया कि मुख्य समारोह स्थल एथलेटिक्स स्टेडियम में एक लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था. मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने अपने 300 सदस्यों की टीम के साथ संगीत का जादू बिखेरा. हरिहरन और जावेद अली जैसे मशहूर गायकों ने भी मुलायम के जन्मदिवस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी. इस मौके पर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया गया था.